

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 फरवरी, 2024

मूल्य 50 पैसे



आपके नाम चिट्ठी



जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सच्चे सपूत थे। विपक्ष भी उनकी सोच का लोहा मानता था। जब बोलते थे तो सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। निर्विवाद और साफ सुधरी छवि रही उनकी।

सदैव देश हित में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया उन्होंने। शांति और शक्ति के प्रतीक थे वह। पोंकरण में परमाणु परीक्षण कर उन्होंने पूरे विश्व को चौंका दिया था। भारत परमाणु सम्पन्न देश बन गया। अनंत प्रतिभाओं के धनी थे अटलजी। निर्मल और स्वच्छन्द स्वभाव उनकी खासियत थी....।

देश में हर साल उनकी जयंती पर 25 दिसम्बर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 'ग्राम गदर' के दिसंबर 2023 के अंक में उनके द्वारा दिए गए सुशासन के मूल मंत्र को उद्धरित करते हुए प्रदेश में नवनिर्वाचित जन-प्रतिनिधियों एवं पाठकों के समक्ष रखा गया था। मुझे खुशी है कि प्रदेश में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

ने जनता से वादा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के विजन पर चलते हुए 'सरकार गुड गवर्नेंस' देगी।

'ग्राम गदर' के पाठकों के साथ मैं यह साझा करता हूँ कि वर्ष 1983 में पहली बार मुझे अटलजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 'ग्राम गदर' भितीपत्र का पहला अंक लेकर मैं उनके पास गया था। मैं देखता रहा, बड़ी तल्लीनता से उन्होंने 'ग्राम गदर' को पढ़ा।

उन्होंने पूछा तो मैंने बताया था राजस्थान के दूर दराज के गांवों तक समाचार पत्र नहीं पहुंचते। इससे गांव के लोगों को उनके लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती। जिससे वे योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। यह भितीपत्र डाक द्वारा भेजा जा रहा है। डाक विभाग के ई.डी. कर्मचारी (ग्रामीण पोस्टमैन) स्वेच्छा से गांव की चौपाल पर इसे चिपकाते हैं और पढ़े-लिखे गांव के लोग इसे पढ़कर सुनाते हैं। गांव वाले इससे जागरूक होंगे।

यह सब सुनकर उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा था 'सवालिया समाज का गठन इसका खास मकसद होना चाहिए... यह नेक काम है, इससे शासन प्रशासन में सुशासन आएगा'। तभी से उनके इस मंत्र का अनुपालन करते हुए 'ग्राम गदर' भितीपत्र ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी काफी लोकप्रिय है।

बिजली मीटर की रीडिंग लिए बिना क्यों भेजा मनमाना बिल ?

जयपुर स्थित जगतपुरा निवासी विनोद मेहता ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.(जेवीवीएनएल) के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-द्वितीय में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में आयोग को बताया गया कि उन्होंने बिजली का घरेलू कनेक्शन ले रखा है। उनके कभी भी 1000 से 1600 रुपए से ज्यादा का बिल नहीं आया, लेकिन मनमाने तरीके से जुलाई 2015 का बिल 26,890 रुपए का जारी कर दिया।

उन्होंने जेवीवीएनएल के ऑफिस में जाकर अधिकारियों से बिजली मीटर की दुबारा रीडिंग लेने के लिए कहा तो उन्हें बिजली कनेक्शन काटने की धमकी दी गई। धमकी से डरकर उन्होंने बड़ी मुश्किल से बिल राशि जमा करा दी। उन्होंने आयोग से जमा कराई राशि हर्जा-खर्चा सहित वापस दिलाने का आग्रह किया।

मामले कि सुनवाई पर जेवीवीएनएल की ओर से कहा गया कि अंधेरे के चलते मीटर की रीडिंग नहीं ली जा सकी। ऐसे में औसत आधार पर बिल जारी किया गया। बिल में पुराने बिलों की राशि भी समायोजित है। उपभोक्ता आयोग ने रीडिंग लिए बिना मनमाने तरीके से बिल जारी करने को गलत और सेवा दोष माना और जेवीवीएनएल को आदेश दिया कि वह बिल की राशि 26,890 रुपए नौ फीसदी ब्याज सहित परिवादी विनोद मेहता को लौटाए। साथ ही उन्हें हुई परेशानी की एवज में 15 हजार रुपए हर्जाना भी अदा करे।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार, 2023

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भिती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 42 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ट पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2023 का विषय जिस पर उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही है, वह है:

'जलवायु परिवर्तन का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव'

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

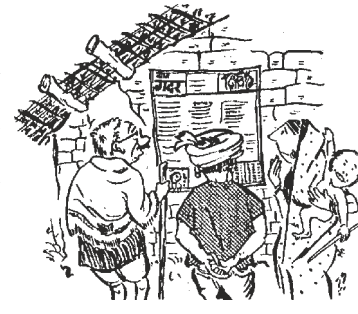
- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। ● टेलीफोन/मोबाइल नम्बर
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2023 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2024 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर

302016 (राजस्थान), फोन: 0141-2282821, फैक्स: 0141-2282485, 4015395

ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाइट: www.cuts-international.org



हर महिला हो सबला और सशक्त

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने जैसलमेर में लखपति दीदी कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा है कि कोई भी देश अपनी आधी आबादी की उपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ सकता

है। यदि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो तो भारत की जीडीपी में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

उन्होंने कहा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का हमारा लक्ष्य है और इसके लिए हर महिला को सबल और सशक्त होना आवश्यक है। स्वयं सहायता समूह वंचित तबके को खासतौर पर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि महिला वह शक्ति है जो पूरे विश्व का हित सोचती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 11.24 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना से लाभान्वित किया जाएगा।



योजनाओं के लिए नहीं धन की कमी

राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में केंद्र से रिलीव होकर आए आईएस अफसर सुधांशु पंत ने कहा है कि प्रदेश में केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। केंद्र और राज्य का निश्चित रूप से अच्छा समन्वय रहेगा।

उन्होंने कहा मैं नहीं समझता किसी तरह की कोई परेशानी आएगी, बल्कि केंद्र को खुशी होगी यदि हम अपनी राशि समय पर खर्च कर सकें। जो भी केंद्र सरकार से मांग की जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है कि वह मिलेगी। प्रदेश हित में जो भी निर्णय होंगे, उनको लिया जाएगा। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए जो भी कदम होंगे उठाए जाएंगे।

जैविक खेती पर हो फोकस

अब फिर से जैविक खेती का चलन बढ़ रहा है। किसान भी समझने लगे हैं कि हमारे खाद्य पदार्थों और खेती में जहरीले रसायनों व कीटनाशकों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

जैविक खेती उनके लिए समृद्धिदायक और मिट्टी के लिए फायदेमंद है। साथ ही साथ जब बड़े पैमाने पर जैविक खेती होने लगेगी तो जैविक उत्पाद उचित दामों में मिलने लगेंगे और उपभोक्ताओं तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। देश के कई राज्यों में किसान जैविक खेती को अपनाकर लाभान्वित हो रहे हैं। उपभोक्ताओं का भी पिछले कुछ वर्षों से जैविक उत्पादों के प्रति रुझान बढ़ा है।

गरीबों का गेहूं हो गया गायब

खाद्य विभाग के अफसरों और ठेकेदारों के गठजोड़ से जयपुर जिले में खाद्य सुरक्षा योजना का पिछले तीन महीनों में ही 41 हजार 825 क्विंटल गेहूं गायब हो गया। यह गेहूं ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को बांटा जाना था। बाजार भाव के अनुसार इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है।

विभाग के अफसरों ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं की। गौरतलब यह है कि यह तो सिर्फ एक जिले का मामला है। अन्य जिलों में जांच हो तो ऐसे कई मामले सामने आ सकते हैं। प्रदेश में बनी नई सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी सख्त हैं। अब सरकार राज्य के सभी जिलों में जांच कराने की तैयारी में जुटी है।



जल जीवन मिशन में हुए घोटाले

सरकार बदलते ही जल जीवन मिशन में हुए घोटालों की पोल खुलने लगी है। अब जमीन में बिछाए गए लोहे के पाइप की जगह प्लास्टिक के पाइप बाहर आने लगे हैं। योजनाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच में भ्रष्टाचार की परतें उधड़ना शुरू हो चुका है।

जयपुर में बस्सी और तुंगा क्षेत्र के गांवों में 34 किलोमीटर की पाइपलाइन तो कागजों में ही बिछा दी गई। जांच में पता लगा कि लाइन तो सिर्फ 5 किमी तक ही बिछी है और ठेकेदारों को करोड़ों रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। बस्सी तुंगा ब्लॉक के कई गांवों में भी गड़बड़ियां सामने आई हैं। प्रदेश के सभी जिलों में जांच हो तो इंजीनियरों व ठेकेदारों की मिलीभगत से हुए करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आ सकता है।

फर्जी सिम लेने पर जेल और जुर्माना

टेलीकॉम बिल 2023 लोकसभा में पास हो गया है। अब इस बिल को राज्य सभा में भेजा गया है। इस बिल में सिम कार्ड का दुरुपयोग रोकने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। फर्जी सिम लेने पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है।

टेलीकॉम कंपनियां बिना ई-केवाईसी के ग्राहकों को नए सिम कार्ड जारी नहीं कर सकेंगी। सिम कार्ड खरीदने के लिए बायोमेट्रिक पहचान को अनिवार्य किया गया है। यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को टेकओवर, मैनेजमेंट या उसे सरपेंड करने की अनुमति देता है।

जरूरत पड़ने पर सरकार किसी भी व्यक्ति का मैसेज ट्रैक कर सकती है और ट्रांसमिशन रोक सकती है। जनहित में सरकार टेलीकॉम कंपनियों को कोई भी मैसेज भेजने का निर्देश दे सकती है। बिल में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने, फाइबर काटने, टावर तोड़ने पर 2 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और सजा का प्रावधान भी है।

प्रधानमंत्री ने दिया 'गुड गवर्नेंस' का मंत्र

भजनलाल सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचन्द बैरवा के पास सबसे ज्यादा विभाग हैं।

अन्य मंत्रियों को भी कई विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 58वें पुलिस महानिदेशक व महानिरीक्षक सम्मेलन में शामिल होने के लिए तीन दिन जयपुर प्रवास पर रहे।

पहले दिन ही वे भाजपा कार्यालय आए और भाजपा विधायकों, मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों की बैठक में गुड गवर्नेंस व लोकसभा चुनाव में जीत के लिए अंत्योदय का मंत्र दिया। इसमें समाज की अंतिम पंक्ति तक योजनाओं के लाभ पहुंचाकर सफलता हासिल करने की बात शामिल है।

उन्होंने नेताओं से वन-टू-वन बात की और केंद्र की योजनाओं व संगठन के कार्यक्रमों को गति देने का संदेश दिया। विधायकों और मंत्रियों को कहा है कि 'हर महीने एक गांव में जाओ और रुको। आप अपना टिफिन भी साथ लेकर जाओ। वहां कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मिलो। गांव वालों की तकलीफ भी समझो।' माना जा रहा है कि इससे सरकारी दफ्तरों एवं मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल की कार्यशैली में इसका असर देखने को मिलेगा।